

पृष्ठ 4

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
संख्या: 596/VII-2/311-उद्योग/2007
देहरादून: दिनांक: 02 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-11/औ0वि0/07-उद्योग/2004 तथा शासनादेश संख्या-940/औ0वि0/07-उद्योग/2004-05 दिनांक 9/10 नवम्बर, 2004 द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान के अधिसूचित किये जाने विषयक जारी नीति/दिशा निर्देशों के अधीन उद्योग निदेशालय की संस्तुति पत्रांक: 532/उ0नि0-नि0औ0आ0/2007-08 दिनांक 16 मई, 2007 के संन्दर्भ में मै0 उत्तराखण्ड इण्डिस्ट्रियल पार्क हेतु ग्राम महुवाखेड़ागंज, तहसील काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर में कय अनुबन्धित/नोटराइज्ड कय अनुबन्धित कुल 83.67 एकड़ भूमि जिसके खसरा नंबर निम्न तालिका में अंकित हैं, को निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निजी औद्योगिक आस्थान के रूप में विनियमित/अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

राजस्व ग्राम का नाम	खसरा नंबर	भूमे का क्षेत्रफल (एकड़ में)
महुवाखेड़ागंज	907, 908, 909, 914मि0, 910, 911, 912, 913, 914,मिन्, 916मि0 Under Negotiation, 918, 919, 944मि0, 945मि0, 946मि0, 947मि0, 948मि0,	83.67
कटैया तहसील काशीपुर	10, 11, 12, 13, 14मि0, 15मि0, 16, 17, 18, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 24,25,	

1. उक्त आस्थान के अन्तर्गत ग्राम-महुवाखेड़ागंज के अन्तर्गत अहरपुरा तोल् में 61.86 एकड़ भूमि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या-50/2003 सी0ई0 दिनांक 10, जून, 2003 के Annexure-II में जिला ऊधमसिंहनगर के अन्तर्गत Category-B Proposed Industrial Estate/Area के अन्तर्गत अधिसूचित हैं, जिन पर स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयो (नकारात्मक सूची के क्रियाकलापों को छोड़कर) को भारत सरकार, के द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा। ग्राम-कटैया स्थित 21.81 एकड़ भूमि में केवल भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1(10)/2001-एन0ई0आर0 दिनांक 7 जनवरी, 2007 के Annexure-II में दिये गये थ्रस्ट उद्योगों की स्थापना ही विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

2. GIDCR-2005- के पृष्ठ संख्या-34 से 37 में औद्योगिक आस्थान के विकास के लिये दिये गये मानकों विधियों/उपविधियों व उपबन्धों का पालन करना होगा।

3- प्रश्नगत औद्योगिक आस्थान की भूमि, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमतः भूमि कय विलेख पत्र (Sale Deed) निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा तथा तत्पश्चात औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भवन मानचित्र उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना होगा।

4- औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। आवंटी इकाईयों को आवंटन से पूर्व आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के संबंध में स्पष्ट सभी सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

5- आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

6- निजी औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा: प्रदेश की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत ऐसी औद्योगिक इकाईयों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किये जा रहे उद्योगों अथवा प्रतिबन्धित सूची के सम्मिलित उद्योगों की स्थापना नहीं की जायेगी।

7- प्रस्तावित स्थल पर सभी अवस्थापना सुविधाओं, यथा: बिजली, पानी, सड़क, नालियों का निर्माण इत्यादि के विकास का कार्य स्वयं प्रवर्तक द्वारा किया जायेगा।

8- प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत रोजगार प्रदेश के स्थायी लोगों को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की सेलडीड/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

9- प्रवर्तक कम्पनी द्वारा आस्थान में भूखण्डों की निर्धारित की गई दरों, विपणन तथा विकास आदि के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, उद्योग उत्तराखण्ड को समय-समय पर सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

11- उपरोक्त उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने पर अथवा किसी कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से यह अधिसूचना (नोटिफिकेशन) निरस्त किया जा सकता है।

12- निजी औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(पी0सी0शर्मा)

प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 5996 (1)/VII-2/311-उद्योग/2007 तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति संवर्द्धन विभाग), उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य ऊर्जा निगम, ऊर्जा भवन, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
8. अध्यक्ष, समस्त उद्योग संघ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
10. प्रबन्ध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
13. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, ऊधमसिंहनगर।
14. श्री अजय गोयल प्रवर्तक, प्रथम तल, भारतीय टूरिस्ट ढाबा, मुरादाबाद रोड, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर।
15. NIC, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(पी0सी0शर्मा)

प्रमुख सचिव।